*नए दशक में वित्तीय क्षेत्र**

शक्तिकान्त दास

आप सभी को हार्दिक सुप्रभात। टाइम्स नेटवर्क द्वारा आयोजित इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2021 में यहाँ होना मेरे लिए वास्तव में सम्मान की बात है। विशेषत: 2019 में इस कार्यक्रम में सहभागिता के एक समृद्ध अनुभव के बाद मैं इस वर्ष के सम्मेलन में भाग लेने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करता रहा हूँ। इस वर्ष के सम्मेलन का थीम ऐसा है जिसकी अनुगूँजें प्रबल हैं- "भारत का दशक: सुधार। प्रदर्शन। रूपांतरण।" कोविड-19 महामारी ने हमारे कर्म जीवन से लेकर हमारी नीतिगत प्राथमिकताओं तक, हमारे आस-पास के हर क्षेत्र में परिवर्तन के चक्र चलायमान कर दिए हैं। एक आधुनिक और रूपांतरित भारत के रूप में उभरने के उद्देश्य से जब हम कोविड -19 द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से निपटने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे प्रासंगिक विषय का चयन करने में टाइम्स नेटवर्क की दूरदर्शिता की मैं सराहना करता हूँ।

आज अपने संबोधन में, मैंने बोलने के लिए एक ऐसा विषय चुना है जिसमें रिजर्व बैंक की एक बड़ी हिस्सेदारी है - "नए दशक में वित्तीय क्षेत्र"। प्रसंगवश, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के विपरीत जब वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियों ने वास्तविक क्षेत्र को प्रभावित किया था, इस बार संक्रमण का जोखिम वास्तविक क्षेत्र से वित्तीय क्षेत्र की ओर है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

वैश्विक स्तर पर, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद पिछले दशक में शुरू किए गए उपायों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ लीवरेज को कम करना और पूँजी की गुणवत्ता व मात्रा में सुधार करना था। नतीजतन, कोविड महामारी के दौर के पहले, बैंक अच्छी तरह पूँजीकृत थे और उच्च तरलता (चलनिधि/ लिक्विडिटी) बफर बनाए हुए थे, तथा इसके साथ ऋण स्थगन और आस्ति वर्गीकरण विराम (फ्रीज) ने मिलकर उन्हें ऐसे कठिन काल में सुदृढ़ बने रहने में मदद की। केंद्रीय बैंकों और राष्ट्रीय सरकारों द्वारा किए गए उपाय जैसे नीतिगत दरों में कमी; पूँजी, चलनिधि (तरलता) और विनियामकीय शिथिलीकरण; आस्ति क्रय; विदेशी मुद्रा स्वैप; और सरकारी गारंटियों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, भारी बिकवाली को रोकने और बैंक बैलेंस शीट की रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सामूहिक प्रयास के परिणामस्वरूप वित्तीय क्षेत्र को स्थैर्य मिला और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह को बनाए रखने में तरलता (लिक्विडिटी) का आवश्यक अवलंब मिला। वैक्सीन में तेजी से प्रगति ने वैश्विक परिदृश्य को बेहतर किया है, पर जिस तरह से वायरस के नवीनतर रूपों की ताजा लहरें नई समस्याएं ला रही हैं हम अभी भी मुश्किलों से बाहर नहीं निकले हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था जहाँ इस अभूतपूर्व आघात के प्रभाव से जूझ रही है, दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों के समन्वित हस्तक्षेप के कारण निकट अवधि के वित्तीय स्थिरता जोखिमों पर लगाम लगाई गई है।

वर्तमान महामारी बैंकिंग प्रणाली में मजबूत पूँजी बफर की अनिवार्यता को रेखांकित करती है। जीएफसी के बाद किए गए पूँजी सुधारों ने मौजूदा महामारी के तत्काल प्रभाव को कम करने अवकाश दिया तो है, पर दोनों उद्देश्यों – गिरावट के कुछ प्रभाव को झेलने के साथ-साथ क्रेडिट प्रवाह को बनाए रखने - के लिए बैंकों को अपनी पूँजी को मजबूती देनी होगी विशेषत: जब मौद्रिक और राजकोषीय उपाय समेटे जाएंगे। वैश्विक विनियामकीय सुधार एजेंडा का एक हिस्सा जहाँ अभी भी कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, महामारी विभिन्न सुधार उपायों के प्रभाव का परीक्षण और मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करती है। संभव है संकट के सबक से बैंकों और वित्तीय क्षेत्र की अन्य संस्थाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय विनियामकीय संरचना के स्वरूप में ध्यान देने लायक नए क्षेत्रों का पता लगे।

भारतीय संदर्भ

भारतीय संदर्भ में, बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखना नीतिगत प्राथमिकता बनी हुई है। जैसा कि मैंने पहले कई मौकों पर जोर दिया है, बैंकिंग प्रणाली की ताकत उसके पूँजी आधार के निर्माण के साथ -साथ कॉरपोरेट अभिशासन और सदाचार-आधारित अनुपालन संस्कृति पर बल देने पर निर्भर करती है।

* नई दिल्ली में टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2021 में गुरुवार, 25 मार्च, 2021को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास का संबोधन

बैंकों और एनबीएफसी को जोखिमों की शीघ्र पहचान करने, उन्हें मापने, जोखिम को असक्रियता से कम करने और संभावित हानि को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त प्रावधानीय बफर बनाने के लिए अपना कौशल बढ़ाना होगा। वे अत्यधिक परंतु संभाव्य दबाव परिदृश्यों के साथ अपने आंतरिक दबाव परीक्षण ढांचे को भी बेहतर करें। आईटी आधार-संरचना का उन्नयन और साइबर सुरक्षा उपायों के साथ ग्राहक सेवाओं में सुधार अन्य प्रमुख मुद्दे हैं और इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

अपनी ओर से, हम आरबीआई द्वारा बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के पर्यवेक्षण को पुनर्संरचित करते हुए इनको एक छत्र के तले लेकर आए हैं और इन संस्थाओं पर पर्यवेक्षी निगरानी को मजबूत करने लिए कई कदम उठाए हैं। हमारा जोर जोखिमों की शीघ्र पहचान, एक व्यवस्थित प्रारंभिक पर्यवेक्षी हस्तक्षेप संरचना को स्थापित करने और लक्षणों की तुलना में कमजोरियों के मूल कारणों पर ध्यान देने पर अधिक है। हम बैंकों और एनबीएफसी में पर्यवेक्षी कड़ाई में भी सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं।

रिज़र्व बैंक इन क्षेत्रों की सुदृढ़ता के उन्नयन हेतु हर तरह की सहायता के लिए भी कदम उठा रहा है। लक्ष्यित दीर्घावधि रिपो (टीएलटीआरओ) और विशेष तरलता समर्थन (स्पेशल लिक्विडिटी सपोर्ट) विंडो के माध्यम से चलनिधि समर्थन के अलावा, अन्य उपायों में प्राथमिकता क्षेत्र को आगे ऋण देने के लिए एनबीएफसी को बैंकों के ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण का लाभ, सह-उधार मॉडल को बढ़ावा, वृहत् एक्सपोजर ढांचे के तहत एनबीएफसी में बैंकों के एक्सपोजर के लिए एक्सपोज़र सीमाओं का समंजन, रेटेड एनबीएफसी में एक्सपोजर हेतु बैंकों और कॉरपोरेट्स के जोखिम भार में ताल-मेल (सिंक्रनाइज़ेशन), तथा प्रतिभूतिकरण और समनुदेशन (असाइनमेंट) के लिए न्यूनतम धारण अवधि (होल्डिंग पीरियड) के लिए छूट शामिल हैं। हमने कणीय /बारीक परिपक्वता खंडों (ग्रेन्यूलर मैच्युरिटी बकेट्स) की शुरूआत और एनबीएफसी हेतु चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के लिए सुगम मार्ग (ग्लाइड पाथ) द्वारा चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे को भी मजबूत किया है। जोखिम प्रबंधन के तौर-तरीकों के संवर्धन के लिए, बड़े एनबीएफसी के लिए यह अनिवार्य किया गया कि उनके यहाँ कार्यात्मक रूप से एक स्वतंत्र मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) हो जिसकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्पष्टत: निर्दिष्ट हों। जटिलता और मल्टीपल लीवरेजिंग को दूर करने, जोखिम प्रबंधन और कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं को मजबूत करने और खुलासों द्वारा पारदर्शिता लाने के लिए मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) संबंधी दिशा-निर्देशों को अगस्त 2020 में संशोधित किया गया था। एचएफसी और एनबीएफसी के बीच गैर-विघटनकारी तरीके से नियमों का सामंजस्य करने के लिए अक्टूबर 2020 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के लिए संशोधित नियामक ढांचा जारी किया गया। इसके अलावा, वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, हम उनके लाभांश वितरण और आकार आधारित विनियमन पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

यूसीबी सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं तथा रिजर्व बैंक और सहकारी समितियों के केंद्रीय/राज्य रजिस्ट्रार (आरसीएस) के दोहरे विनियमन के तहत हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) में हाल के संशोधन सहकारी बैंकों के अभिशासन, पूँजी, लेखा परीक्षा और समामेलन के कार्यों को रिजर्व बैंक के विनियामकीय क्षेत्र के अंतर्गत लेकर आए हैं। हाल की अवधि में, हम उनके अभिशासन संरचना में सुधार, प्रणाली-आधारित आस्ति वर्गीकरण मानदंडों को लागू करने, उन्हें सीआरआईएलसी[1] रिपोर्टिंग आधार-संरचना में और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एएसएफ) के अंतर्गत लाने के कदम उठा रहे हैं। पिछले महीने, हमने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जो इन मुद्दों की जाँच करेगी और यूसीबी क्षेत्र को मजबूत करने का रास्ता बताएगी।

बैंकिंग क्षेत्र: आगे की राह

रिज़र्व बैंक अधिक एक प्रतिस्पर्धी, सक्षम और विविधता-पूर्ण बैंकिंग संरचना की दिशा में प्रयासरत है। यूनिवर्सल बैंकों, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीतियां इस दिशा में एक कदम हैं। वर्तमान में, दस एसएफबी

[1] बड़े क्रेडिट संबंधी सूचना का केंद्रीय भंडार

और छह भुगतान बैंक कार्य कर रहे हैं।

मैं वर्तमान दशक में बैंकिंग परिदृश्यों के चार अलग-अलग समूहों को उभरते देखता हूँ। प्रथम में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति वाले कुछ बड़े भारतीय बैंकों का दबदबा होगा। द्वितीय में, कई मध्यम आकार के बैंक होंगे जिनकी उपस्थिति पूरे अर्थव्यवस्था में होगी। तृतीय समूह में निजी क्षेत्र के अपेक्षाकृत छोटे बैंक, एसएफबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक शामिल होंगे, जो विशेष रूप से छोटे उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करें। चौथे वर्ग में डिजिटल खिलाड़ी शामिल होंगे जो ग्राहकों के लिए सीधे सेवा प्रदाता के रूप में या बैंकों के माध्यम से उनके एजेंट या सहयोगी के रूप में कार्य कर सकते हैं। वास्तव में, डिजिटल खिलाड़ी तेजी से सभी वर्गों में महत्वपूर्ण हिस्सों के रूप में उभरेंगे।

आइए अब मैं उन पारस्परिकताओं और सहऊर्जस्विताओं की चर्चा करता हूँ जिनका दोहन इन चार वर्गों द्वारा एक दूसरे से आगे निकलने की स्पर्धा में क्रम में संभावित है। इनमें से प्रत्येक को समाज की भविष्य की जरूरतों को समझने और भारतीय वित्तीय क्षेत्र में विकास के अनुसार कार्रवाई की जरूरत है। लेनदेन की संख्या में भारी वृद्धि को संभालने के लिए आईटी प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उदाहरण साफ़ तौर पर सामने है, जिसमें मासिक लेनदेन की गिनती 1 बिलियन तक पहुँचने में तीन साल (2017-2019) लगे, लेकिन दोगुना होकर 2 बिलियन प्रति माह होने में इसे एक और वर्ष की छोटी अवधि ही लगी। यह प्रणाली (सिस्टम) और माध्यम (प्लेटफॉर्म) की वर्धमानता/मान संयोजत्व (स्केलेबिलिटी) की आवश्यकता को कुछ इस तरह दर्शाता है कि इसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है, वृद्धिशील 'मान संयोजत्व' ('इंक्रिमेंटल स्केलेबिलिटी') नहीं, बल्कि 'घातांकी मान संयोजत्व' ('एक्सपोनेंशियल स्केलेबिलिटी')।

फिनटेक अपनाने की दर में 64 प्रतिशत के वैश्विक औसत की तुलना में भारत 87 प्रतिशत के साथ एशिया का शीर्ष वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) हब बनने की राह पर है। भारत में फिनटेक बाजार का मूल्य 2019[2] में ₹1.9 ट्रिलियन था और डिजिटल भुगतान, डिजिटल ऋण, समकक्षी/पीयर टू पीयर (पी2पी) उधार, चंदा (क्राउड फंडिंग), ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नॉलॉजी, बिग डेटा, रेगटेक और सुपरटेक आदि विविध क्षेत्रों में 2025 तक ₹6.2 ट्रिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। ऐसी दुनिया में जहाँ फिनटेक कंपनियां डिजिटल लेनदेन की मात्रा के मामले में अग्रणी हैं तथा बैंकिंग व वित्त उद्योग में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, यह महत्वपूर्ण है कि वाणिज्यिक बैंक तकनीकी परिवर्तनों के अनुसार ढलें और इन संस्थाओं के साथ मिलकर काम करें ताकि भविष्य में वे व्यापार के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय परितंत्र का हिस्सा बने। किफायती और कुशल मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने में सार्थक सहयोग और सह-अस्तित्व से दोनों क्षेत्रों का भला होगा।

विनियामकीय परिप्रेक्ष्य से, निरंतर ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से प्रभावी विनियमन का संवर्धन आरबीआई की प्राथमिकता है ताकि हम दो कदम आगे रहें। रिज़र्व बैंक का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि विनियम नवाचार को बाधित न करें; बल्कि वे वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता, साइबर सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण आदि की आवश्यकता से समझौता किए बिना नवाचार को प्रोत्साहित और पोषित करें। विनियमन और पर्यवेक्षण में इष्टतमता महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हमने हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण सहित डिजिटल ऋण देने पर एक कार्य समूह का गठन किया है। कुल मिलाकर, फिनटेक के व्यवस्थित विकास से वित्तीय क्षेत्र के सभी हितधारकों को लाभ होगा।

वित्तीय क्षेत्र और भुगतान प्रणाली - अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा

हम जब फिनटेक और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, तो भुगतान प्रणालियों में घटनाक्रम पर चर्चा अत्यंत प्रासंगिक होगी जहां भारत ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। जैसा कि कहावत है "भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है भविष्य का सृजन " और रिज़र्व बैंक में, भुगतान प्रणालियों के भविष्य की बात करें तो हम इस तरीके पर अटल हैं। नवोन्मेष को बढ़ावा देने और उपयोगकर्ताओं को अत्याधुनिक और सुरक्षित अनुभव प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ, हमने वैश्विक स्तर पर भुगतान प्रणालियों में खुद को सबसे आगे

[2] *https://www.researchandmarkets.com/reports/5024695/fintech-market-in-india-2020.*

रखा है। जब भुगतान प्रणाली के मामले में भारत अग्रणियों में से एक के रूप में उभरा है; शायद कोविड वैक्सीन में मान्यता के मोर्चे की तरह इस स्थिति को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण और रोमांचक दोनों है।

भारतीय भुगतान प्रणाली की वृद्धि दर अभूतपूर्व रही है, जो आए दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। भारत में डिजिटल भुगतान की मात्रा पिछले पांच वर्षों में 55 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर से 2015-16 में 5.9 बिलियन से बढ़कर 2019-20 में 34.3 बिलियन हो गई, जो 5 वर्षों में लगभग छह गुना है। यूपीआई और आधार सक्षम भुगतान सेवा (एईपीएस) जैसी खुदरा भुगतान प्रणालियों ने खुदरा भुगतान प्रणालियों की संपूर्ण समीकरण को बदल दिया है क्योंकि उनका उपयोग देश के कोने-कोने में किया जा रहा है। पिछले साल जब लोगों को वित्तीय प्रोत्साहन की प्रक्रिया में कई कई दूसरे राष्ट्र चेक लिख रहे थे, तब भारत में हमने लोगों को सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए 274 करोड़ डिजिटल लेनदेन प्रोसेस किए।

24x7 और अंतरपरिचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) दो प्रमुख पहलू हैं जो हमारी भुगतान प्रणाली की पहचान हैं और रहेंगे। यदि मौजूदा आधार-संरचना का इष्टतम उपयोग करना है तो इंटरऑपरेबिलिटी अपरिहार्य है। कम पैठ वाले क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान आधार-संरचना का विस्तार करने के लिए भुगतान आधार-संरचना विकास कोष [पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ)] की स्थापना में आरबीआई की हालिया पहल का उद्देश्य भुगतान को अधिक समावेशी बनाना है। रिज़र्व बैंक का जोर इस पर है कि हमारी सभी भुगतान प्रणालियां चौबीसों घंटे, वर्ष में 365 दिन कार्य करें और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 24x7 एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम के साथ, हम उन गिने-चुने देशों में से हैं जो किसी भी समय कोई भी राशि स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

भारत में यूपीआई की सफलता को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अत्यधिक प्रशंसा मिली है और दुनिया भर के कई देशों ने इसी तरह की प्रणाली विकसित करने में रुचि दिखाई है जो मजबूत द्विपक्षीय व्यापार संचालन और आर्थिक साझेदारी का आधार प्रदान कर सकती है। बहुपक्षीय सीमा-पारीय भुगतानों के लिए भी उपलब्ध साधनों के मुकाबले यूपीआई प्रणाली में सस्ते और तेज विकल्प के रूप में भी सामने आने की क्षमता है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि हमारे आरटीजीएस में बहु-मुद्रा क्षमताएं भी हैं और अब 24x7 संचालन के साथ, यह टटोलने की गुंजाइश है कि क्या इसके पदचिन्हों को भारत के पार बढ़ाया जा सकता है। नवोन्मेष को बढ़ावा देने में रिजर्व बैंक के अग्रणी होने के को देखते हुए वह दिन दूर नहीं, जब सीमा पार धन प्रेषण का हमारा अनुभव अधिक सस्ता, तीव्रतर और अधिक सुरक्षित होगा। इसके अलावा, स्वदेशी रुपे कार्ड नेटवर्क ने सभी स्तरों पर आश्चर्यजनक वृद्धि दिखाई है और बाजार में इसकी हिस्सेदारी अच्छी है। रुपे की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति के साथ, हमारा घरेलू कार्ड नेटवर्क आगे चलकर वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में अपनी छाप छोड़ सकता है।

रिज़र्व बैंक एक ऐसा परितंत्र विकसित करने का सघन प्रयास कर रहा है, जो न केवल भविष्य की प्रौद्योगिकियों का पोषण करेगा, बल्कि वित्तीय समुदाय की तकनीकी आकांक्षाओं को भी प्रोत्साहित करेगा। इस दिशा में, भारत में फिनटेक के विकास में आगे बढ़ते हुए, अगस्त 2019 में रिज़र्व बैंक कुछ चुनिंदा देशों के विशिष्ट वर्ग में शामिल हो गया, जिनका अपना विनियामकीय परीक्षण क्षेत्र (सैंडबॉक्स) परितंत्र है, जहाँ कोई भी विनियमित या अविनियमित संस्था आ सकती है और नियंत्रित वातावरण में अपने अभिनव उत्पादों या सेवाओं का लाइव परीक्षण कर सकती है। यह विनियामक, नवोन्मेषकों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं (ग्राहकों) के बीच एक सहयोग है जो यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय उपभोक्ताओं को अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सेवाएं प्राप्त होती रहें। "खुदरा भुगतान" पर प्रथम समूह (कोहोर्ट) और "सीमा पार से भुगतान" पर द्वितीय समूह पर मिले प्रतिसाद उत्साहजनक थे। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने अपना स्वयं का नवोन्मेषण केंद्र/हब (आरबीआईएच) भी बनाया है। यह हब वित्तीय नवाचारों से संबंधित विचारों के आदान-प्रदान और प्रोटोटाइप के विकास के लिए वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों, प्रौद्योगिकी उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करेगा। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) और कई केंद्रीय बैंकों ने भी प्रौद्योगिकी आत्मसात करने में आगे रहने के लिए ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं।

इस प्रक्रिया में, हमें कुछ तकनीकी नवोन्मेषों से जुड़े जोखिमों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में, जब हम वैध (फिएट) मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण लाने पर काम कर रहे हैं, रिजर्व बैंक यह भी आकलन कर रहा है कि इस तरह की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) लाने से वित्तीय स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। चूँकि अंतर्निहित तकनीक अभी भी विकसित हो रही है, हम एक स्पष्ट, सुरक्षित और कानूनी रूप से निश्चित निपटान के लिए तरीके तलाश रहे हैं, जो एक सुरक्षित और कुशल भुगतान प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह बात भी समझी जानी चाहिए कि दुनिया भर में सीबीडीसी के संचालन के व्यावहारिक उदाहरण अधिक नहीं हैं; इसमें अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि हम एक सुरक्षित और मजबूत मॉडल तैयार कर सकें।

जब डिजिटल नवाचारों की बात आती है तो साइबर सुदृढ़ता बढ़ाना एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने ऑपरेटिंग घंटे बढ़ा रहे हैं और अधिक पहुंच एवं अधिक अंतरपरिचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) की इजाजत दे रहे हैं, हमारे सिस्टम पर साइबर हमलों के खतरे लगातार हैं। अनुभव से पता चलता है कि सबसे कुशल और संरक्षित प्रणालियों को भी भेदा जा सकता है जो हितधारकों के सामने असंगत जोखिम ला सकता है। रिजर्व बैंक लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है और बैंकों और बैंकेतर इकाइयों को ऐसे हमले रोकने वाली क्षमताएं स्थापित करने और बनाए रखने को प्रोत्साहित कर रहा है। यह भी पता होना चाहिए कि इस तरह के हमले होने पर उन्हें कैसे रोका जाए और कैसे तेजी से मरम्मत कर प्रणाली (सिस्टम) को सामान्य स्थिति में पुनर्स्थापित किया जाए। आवधिक परीक्षणों और अभ्यासों (ड्रिल्स) द्वारा प्रणालियों की साइबर क्राइसिस (संकट) प्रूफिंग आवश्यक है।

फिनटेक के बढ़ते डिजिटलीकरण और विकास के साथ, यह प्रत्याशित है कि क्रेडिट मूल्यांकन के पारंपरिक तरीकों के स्थान पर नए युग के क्रेडिट मूल्यांकन विधियां आएं जिसमें गैर-वित्तीय और विश्वसनीय लेनदेन डेटा पर ध्यान हो। कई फिनटेक फर्मों ने पहले ही इस तरह की पद्धति अपनाई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में, यह विशिष्ट के बजाय मुख्यधारा अधिक होगी। इससे वित्तीय समावेश के उद्देश्य को और बल मिलेगा। तथापि, साथ ही, यह डेटा गोपनीयता, सहमति और सुरक्षा की चिंताओं के मामले में कई नई चुनौतियां खड़ी करता है। इन चिंताओं से पार पाने में भुगतान मूल्य श्रृंखला में हितधारकों का नैतिक व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का जवाब देने में वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं की क्षमता उनके प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक बन सकती है।

समापन टिप्पणियां

वित्तीय सेवाओं की गतिशील दुनिया में, और इससे भी अधिक महामारी के बाद, उम्मीद है कि वित्तीय क्षेत्र को फिनटेक नवाचारों और अपनी घातीय वृद्धि से चुनौती देगा। ग्राहक सेवाओं के लिए फिनटेक का उपयोग प्रभावी रूप से लागत को नियंत्रित करेगा और बैंकिंग और गैर-बैंकिंग व्यवसायों का विस्तार करेगा। कोविड-19 के फलस्वरूप डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग से मौजूदा दशक में डिजिटल ऋण में वृद्धि हो सकती है जब कंपनियां उपभोक्ता डेटा जमा कर रही हैं और क्रेडिट एनालिटिक्स को बढ़ा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिरता, प्रतिस्पर्धा और डेटा सुरक्षा के बीच नए और जटिल संतुलन की चुनौती सामने आ रही है; जिसे देखते हुए, नए विनियामक ढांचे और निगरानी के नए तरीकों की आवश्यकता है। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के लिए वैश्विक घटनाक्रम की निगरानी तथा जोखिमों व अवसरों के अनुसार नीतिगत प्रत्युत्तर तैयार करना अनिवार्य है।

आगे, बैंकों को अर्थव्यवस्था के पारंपरिक क्षेत्रों के महत्त्व को कमतर किए बिना नए उदीयमान क्षेत्रों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है। यह कॉन्क्लेव हमें पलटकर यह देखने का अवसर देता है कि क्या हासिल हुआ है और इस पर विचार का कि अभी भी क्या किया जाना शेष है। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि महामारी के कमजोर पड़ने वाले प्रभावों से अर्थव्यवस्था को मजबूती से उबारने के लिए रिजर्व बैंक में हम अपने समस्त नीतिगत साधनों के प्रयोग के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। रिज़र्व बैंक वित्तीय क्षेत्र को विकसित करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए वृद्धि की पूर्वापेक्षाओं के सृजन हेतु एक समर्थक परिवेश के निर्माण के लिए समर्पित है।